

क्या बंगाल में भाजपा का “ट्रंप कार्ड” साबित होंगे नए अध्यक्ष नितिन नबीन

बंगाल में भाजपा ने “भद्रलोक” (जिसमें कायस्थ अधिक हैं) वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में एक “ट्रम्प कार्ड” के रूप में उभरेंगे, जहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनावों के सबक पश्चिम बंगाल में भाजपा के काम नहीं आयेंगे। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 0.1 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2021 के पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वोट शेयर 10 प्रतिशत अधिक था। बिहार में भाजपा की सफलता में छोटे दलों, जिनमें एलजेपी (आरबी) शामिल है, के साथ गठबंधन का बड़ा योगदान था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ

- बंगाल में हालांकि भद्रलोक के वोटर्स की संख्या कम है पर वे आम वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की कई नामचीन हस्तियां इसी वर्ग से आती हैं, जैसे, स्वामी विवेकानन्द, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, ज्योति बसु, सत्यजित रे, बिमल मित्र आदि।
- बिहार में भाजपा के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन में मात्र 0.1 प्रतिशत का वोट अंतर था पर बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर भाजपा से 10 प्रतिशत अधिक है। बिहार के विपरीत यहां भाजपा को छोटे-छोटे दलों का सहारा भी नहीं है।
- सवाल यह है कि क्या भद्रलोक को साधकर भाजपा तृणमूल के आसपास पहुंच पाएगी?

केवल वामपंथी और कांग्रेस ही अन्य प्रमुख दल हैं, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के भी छोटी-मोटी संख्या में ही चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। ममता

बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला वोटर्स पर काफी मजबूत पकड़ है। तो, भाजपा इन चुनौतियों से कैसे काबू पायेगी।

जाहिर है, भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प, टीएमसी के साथ ही, वामपंथी और कांग्रेस के मूल समर्थन आधार को साधना है और उन ‘भद्रलोक’ वोटर्स की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना है, जो संख्या में कम होते हुए भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वह जगह है, जहाँ नबीन, जो कि कायस्थ जाति से हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है।

बंगाल के कायस्थ, जो शिक्षित और प्रभावशाली हैं, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करते हैं। जाने-माने बंगाली कायस्थों में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, चितरंजन दास, सत्यजीत रे, बिमल मित्र, जैमिनी राय, अमर्य सेन और सर जदुनाथ सरकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नये कार्यकारी अध्यक्ष, अपने जमीनी दृष्टिकोण के साथ, इस वर्ग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की सफलता के बीच गडकरी फिर विवादों में

उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटों को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत की 20 प्रतिशत ऐथेनॉल मिश्रण नीति (ई 20) को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से हितों के टकराव के आरोपों, वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं और राजनीतिक विरोध पर केन्द्रित है।

उन पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में सबसे अहम हितों के टकराव का है। सितंबर 2025 में कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी ने सरकारी नीति का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए किया।

आरोपों के अनुसार, उनके बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की आयवित्तवर्ष 2024

- एक विवाद यह भी है कि ऐथेनॉल युक्त पेट्रोल-डीज़ल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और वाहनों का माइलेज भी घट गया है।
- लेकिन नितिन गडकरी इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल लॉबी पैसे देकर उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार करवा रही है।

की पहली तिमाही में 17.47 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

इसी तरह, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी द्वारा संचालित मानस एग्रो इंडस्ट्रीज भी ऐथेनॉल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की एक बड़ी कंपनी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि ई20 ईंधन को पूरे देश में तेजी से लागू किए जाने के कारण इन कंपनियों को असाधारण मुनाफा हुआ।

वाहनों के प्रदर्शन को लेकर भी

गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कई उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ई20 पयूल कोरोसिव (संश्लारक) प्रकृति का है और अप्रैल 2023 से पहले बने वाहनों के इंजनों की उम्र कम कर सकता है। कुछ रिपोर्टों में माइलेज में 3 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट और पयूल सिस्टम तथा रबर गैस्केट को नुकसान की आशंका जताई गई है।

नितिन गडकरी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें ‘पेड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आईपीएस पंकज चौधरी के बकाया प्रमोशनों पर प्रोविज़नल तौर पर विचार करें’

जयपुर, 22 दिसंबर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चल रहे प्रमोशन पर प्रोविजनल तौर पर विचार

- केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) ने राज्य सरकार को निर्देश दिये।

करे। अधिकरण ने यह आदेश पंकज चौधरी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। इसके साथ ही साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन भी रुका हुआ है। राज्य सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत हिंदू राष्ट्र है’

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि इसके लिए किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है।

आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक रहेगा जब तक देश में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया जाता रहेगा।

भागवत ने कोलकाता में आरएसएस के ‘100 व्याख्यान माला’

- संघ प्रमुख भागवत ने यह दावा करते हुए कहा, संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो भी ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है यह सत्य है।

कार्यक्रम में कहा, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। हमें नहीं पता यह कब से हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी हमें संविधान को मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वह भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीएमसी चुनाव में एक हुई मुम्बई की “फर्स्ट फैमिली”

20 सालों में यह पहली बार है जब उद्धव और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। मुंबई की राजनीति में ‘पहला परिवार’ माने जाने वाले ठाकरे परिवार ने सोमवार सुबह एक बड़े चुनावी पुनर्मिलन की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने होने वाले बृह-मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर इस परिवार में आधिकारिक सहमति बन गई है।

पिछले 20 वर्षों में यह पहला अवसर होगा, जब ठाकरे परिवार के दो सबसे बड़े नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

इस बीच, कांग्रेस इस व्यवस्था का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थिति महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर तनाव को दर्शाती है, खासकर ठाकरे भाइयों के एकजुट होने के बाद। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में एमवीए को झटका लगाने के बाद भी, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वापसी की उम्मीद है।

बड़े संकटों के दौर में, दलितों, मुसलमानों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर, देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा जताया है।

- बीएमसी की 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 157 और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
- इस नई व्यवस्था में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सहयोगी दलों, कांग्रेस व एनसीपी (शरद पवार) को कोई जगह नहीं मिली है इससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित नहीं रहे और भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस ने भी इन चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक हल्की सी चुनौती पेश की।

इस सफलता का श्रेय कांग्रेस नेता विजय वडेड़ीवार, कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रतिभा धनोरकर और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाले को जाता है।

कांग्रेस द्वारा जीते गये कुल 34 नगर परिषद अध्यक्ष पदों में से आठ सीटें चंद्रपुर जिले की और तीन सीटें बुलढाणा जिले की थीं।

विश्वजोत कदम अपने गढ़ को बचाने में सफल रहे, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस विधायक

अमित देशमुख अपनी पकड़ बनाए रखने में असफल रहे।

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने कुल 288 में से 120 नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 56 और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 36 पद मिले।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सूत्रों ने बताया कि शिव सेना बीएमसी की 227 सीटों में से 157 पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि शेष 70 सीटों पर उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने उम्मीदवार उतारेंगी।

इस व्यवस्था के बाद, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना-नेतृत्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, भारत की बड़ी उपलब्धि

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि तय समय से 5 साल पहले ही प्राप्त कर ली गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भारत को ऐथेनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में 20 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्त तय अवधि से पांच साल पहले ही हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात व्यय में कटीती हुई है और यह सतत ईंधन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के पयूल पंपों पर दशकों की सबसे बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। देश का ऐथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम पायलट चरण से राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है, जिसमें ऐथनॉल सप्लाई इयर (ईएसवाय) 2024-25 में ब्लैंडिंग औसतन 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और ईएसवाय 2025-26 में ई 20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथनॉल का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में, ब्लैंडिंग

- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीज़ल) से इकोफ्रेंडली ईंधन के इस्तेमाल की तरफ जाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है।
- ऐथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर है वहीं स्थान पर यूएसए तथा दूसरे पर ब्राज़ील है।

8.10 प्रतिशत से बढ़कर ईएसवाय 2020-21 में 14.60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जब 707.40 करोड़ लीटर ऐथनॉल पेट्रोल में मिलाया गया। बिल्कुल हाल ही में ईएसवाय (नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक) में, 1,022.4 करोड़ लीटर ऐथेनॉल मिलाया गया, जिससे औसतन 19.24 प्रतिशत की ब्लैंडिंग हासिल हुई, जो ई 20 लक्ष्य के बेहद करीब है।

यह जानकारी 8 दिसम्बर 2025 को राज्य सभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी

द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई थी।

इंडियन शुगर एण्ड बायो एनर्जी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) की वार्षिक आम बैठक के दौरान, दीपक बलानी, महासचिव, आईएसएमए ने कहा: “भारत ने ई 20 के लक्ष्य को बहुत तेजी से हासिल किया है। लक्ष्य 2030 तक 20 प्रतिशत ब्लैंडिंग का था, लेकिन हम इसे पांच साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जो काम ब्राजील जैसे देशों ने 20 साल में किया, हमने वह सिर्फ 7-8 साल में कर दिखाया।

ऐथेनॉल ब्लैंडिंग भारत को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत में भी मदद कर रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसम्बर 2025 को संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ऐथेनॉल ब्लैंडिंग की वजह से देश ने 1,55,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इन लाभों के बावजूद, और 2024 में 6.2 बिलियन लीटर ऐथेनॉल का उत्पादन करने के बावजूद, भारत अभी भी वैश्विक नेताओं, अमेरिका और ब्राजील से पीछे है, जैसा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

वैश्विक ऐथेनॉल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत (61.4 बिलियन लीटर) है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वनरक्षक पेपर लीक में लेखाकार व वनरक्षक गिरफ्तार

जयपुर, 22 दिसंबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने वनरक्षक भर्ती-2020 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पेपर पढ़ने वाले लेखाकार सहित वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। अब जाकर एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि उदयपुर व बांसवाड़ा के अलावा जयपुर में भी वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ

- एसओजी ने अपने घर पर लीक पेपर पढ़वाने वाले वनरक्षक तथा लीक पेपर पढ़कर वनरक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया।

था। जयपुर में एक लेखाकार ने अपने घर पर वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया था। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लेखाकार सहित, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वाले वनरक्षक को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साले-बहनोई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्य आरोपी जबराम से पूछताछ में पता चला कि टोडाभीम निवासी लेखाकार अमन जोरवाल ने जयपुर में अपने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घोषणा के साथ ही झटका लगा भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील को

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “बैड डील” करार दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा बड़े जोर-शोर से घोषित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट – एफटीए) को एक उस समय एक तगड़ा झटका लगा, जब सत्ताधारी गठबंधन के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “खराब समझौता” करार देते हुए कहा कि यह “बहुत अधिक देने” तथा “बहुत कम” प्राप्त करने वाला समझौता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को स्वीकरण एक टेलीफोन कॉल के दौरान किया, जो द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है। इस समझौते पर तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद

है और 2026 में यह क्रियान्वित हो जायेगा।

दोनों पक्षों ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बताया, और यह भारत-न्यूजीलैंड एफटीए रिकॉर्ड नौ महीने में पूरा हो गया। इस समझौते की विधिवत बातचीत पीएम लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई थी।

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री पीटर्स ने न्यू दिल्ली और वेलिंगटन के बीच हुए इस एफटीए का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वाली सरकार ने डील में “सबस्टैस” का ध्यान नहीं रखा और शीघ्र डील होने पर ध्यान रखा।

पीटर्स, जो “न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी” के नेता और सरकार में गठबंधन साझीदार हैं, ने कहा कि उनकी पार्टी “खेद सहित” इस समझौते के खिलाफ

- विंस्टन पीटर्स ने कहा, इसमें न्यूजीलैंड को बहुत कुछ देना पड़ेगा पर बदले में उसे बहुत कम मिलेगा। पीटर्स न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, जो न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
- भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने टेलिफोन वार्ता में इस डील की घोषणा की। इस डील पर तीन माह के भीतर हस्ताक्षर होने और इसके 2026 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

है और जब यह संसद में पेश होगा तो वे इसके सक्षम कानून का रूप लेने के खिलाफ मतदान करेंगे।

पीटर्स ने एक्स पर लिखा, “हम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को न तो मुक्त मानते हैं और न ही निष्पक्ष।” उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के आर्थिक और श्रमिक हितों

पीटर्स ने कहा, “प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूजीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूजीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।”

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा सुचित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा बनाने से न्यूजीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।”

मोर का शिकार कर पार्टी करते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

उदयपुर, 22 दिसम्बर (कासं)। जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला गडावत गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है तथा दूसरा हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल पुत्र भगवान मीणा है, तीसरा आरोपी राकेश पुत्र कुरीचंद है। तीनों ही आरोपी एक गांव के हैं।

प्रकरण के अनुसार, रविवार को गश्त के दौरान एसएसआई रमेशचन्द्र को ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला

- श्रृषभदेव थाना पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल प्रेम शंकर मीणा के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल मीणा को भी पकड़ा।

गडावत गांव में नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर पार्टी करने के लिए पकाने की सूचना मिली। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जहां तीनों आरोपी शिकार किए गये राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाते मिले। तीनों को दबोचकर तथा इनके कब्जे से शिकार किए मोर के अवशेष जब्त कर, पूछताछ के लिए थाने लेकर आए।

वन विभाग अधिकारियों को सूचना देने पर वनरक्षक सुमित्रा ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही शुरू की। इधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया। स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी।

। लोग पीड़ी देर पीड़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी।

यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 बनाया। 2009 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

नरेगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी। केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 40 प्रतिशत से अधिक न हो एवं 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 10 प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 40 प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 10 प्रतिशत से भी कम भुगतान पड़ता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं। कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया। उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंगे सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंगे गाड़ी खरीद ली थी। भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था। सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2009 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 15 दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित कराया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजान में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभावी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरों में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

2005 से 2025 तक लगभग 20 वर्ष तक नरेगा अकुशल श्रमिकों के लिए ;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेगा के अंतर्गत देश में कुल 15.5 करोड़ जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 200 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 100 दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 45 दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 125 दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2015 में संसद में नरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 10 वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संख्या बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं। वह इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे? अब तक राज्यों पर 10 प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पड़ता था जो बढ़कर अचानक 40 प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि शर्षों को तोड़ मरोड़ करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख,राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू,राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों की केंद्रीकरण कर दिया है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है। इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 700 किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अरावली पर न्याय का संदेश : संरक्षण जिम्मेदारी का संतुलन



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2009 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थाओं द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 100 मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा।

वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस 500 मीटर जोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों की कसौटी पर नितांत तथ्यहीन हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके कार्यकाल में अरावली के लिए दोस संरक्षण मॉडल विकसित किया जा सकता था, तब कोई निर्णायक पहल नहीं हुई। आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक सख्त, वैज्ञानिक और

814वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह

पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूं, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरूद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री का स्वागत कर दस्तारबंदी कर उर्स की मुबारक दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री

2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आवाहन किया है। उसको पूरा हम सबको मिलकर करना है। आपस में लड़ाई होगी तो मकसद पूरा नहीं होगा। अजमेर शरीफ में आकर दिल को बहुत सुकून मिला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य नेता सहित जिला कलैक्टर लोक बंधु,

जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं। इससे अब दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। बालक की दो किडनी जोधपुर एग्म में एडमिट मरीज को लगाई जाएगी। वहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिबर को दिल्ली के लिए जोधपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से लिबर दिल्ली भेजा गया है।

एग्म के अनुसार, बालोतरा में नाइयों की ढाणी गिडा के रहने वाले भोमाराम (5) पुत्र भैराराम को बार-बार दौरें पड़ने की समस्या पर 15 दिसंबर को एप्स लाया गया था। पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भोमाराम का इलाज शुरू किया। इस दौरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

■ पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिबर दोनों डोनेट किए

स्टेट्स एस्प्लिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग

मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

वृष नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

मिथुन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कर्क परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

तुला घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उसव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अगर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यं महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

■ केंद्रीय मंत्री रिजिजू लेकर पहुंचे अजमेर, बुलंद दरवाजे पर पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया

एसपी वंदिता राणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चित्ताण पासवान की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। दरगाह के खादिम जुहर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। जियारत के बाद अकीदत और सम्मान के साथ चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने बताया कि तेरा सदी के मद्देनजर विश्रामस्थली में ठहरने वाले जायरीन की सुविधार्थ हेतु माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां दुकानें लगाया शुरू हो गई हैं, साथ ही विश्राम स्थली पर ठहरने वालों के लिए अकीदतमद्द ने लंघर शुरू कर दिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। छह दिवसीय उर्स में आने वाले अधिकांश जायरीन उर्स की छटी का कुल की रस्म अदा कर ही लौटेंगे।

सार-समाचार

ग्राम तबीजी में स्वच्छता रैली का हुआ आयोजन

अजमेर, (कासं)। केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना कार्यालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कार्यालय केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना अजमेर द्वारा ग्राम तबीजी में स्वच्छता रथ के माध्यम से एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से कार्यालय प्रमुख बलबीर गैना द्वारा समस्त ठाम वासियों को भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के विषय में जानकारी देते हुए स्वच्छता के विषय में जागरूक किया गया। साथ ही अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छता के माध्यम से भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया। रैली में जन-मानस भी बहु-चढ़ कर सम्मिलित हुए। रैली में लगभग 24 लोग सम्मिलित रहे। इसमें नरेंद्र टाक, रामदेव, खुशहाल जाट, मनीष एवं आशीष टाक ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई।

शुभदा स्पेशल वर्ल्ड में प्री-क्रिसमस पार्टी का आयोजन

अजमेर, (कासं)। कोटड़ा स्थित शुभदा स्पेशल वर्ल्ड में विशेष बच्चों द्वारा प्री-क्रिसमस सेलिब्रेशन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अध्यापकों के साथ मिलकर गिफ्ट, फेयरी बेल एवं स्टार से सजावट करते हुए क्रिसमस ट्री और स्नोमैन को आकर्षक रूप दिया। बच्चों ने सांता की पोशाक पहनकर क्रिसमस गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का माहौल बन गया। कार्यक्रम में सेंट एंसेलब स्कूल के छात्र-छात्राएं एवं इंचार्ज साक्षी, अजिम व जयसन शामिल हुए। छात्रों ने केरल ग्रुप सांनो की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। आर्यन कॉलेज के छात्र-छात्राओं, सांता बने कृष्णा व भव्या, प्रिंसिपल रेनुका तिवारी, अध्यक्ष पार्थ पुरोहित, अध्यापिका संजु, समाजसेवी रेखा शर्मा एवं व्यवसायी केदार शर्मा ने बच्चों के साथ मिलकर बलून डांस किया और क्रिसमस केक काटा। कार्यक्रम में सौफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं अचिता, हरप्रती सहित अन्य ने भी सहभागिता निभाई। म्यूजिकल चैयर, म्यूजिकल ग्लास, रिंग गेम जैसे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी ऊषा कच्छावा, समाजसेवी वीरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, अजमेर होनिस्टी संस्था की अध्यक्ष सुनीता चौहान, सचिव प्रणेश कुमार, लार्यस क्लब से प्रियंका बंसल, रीमा जैन, अनुष्का माहेश्वरी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को अजमेर में

अजमेर, (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का गुरुवार को अजमेर आने का कार्यक्रम है। बागडे सुबह 10.45 बजे महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वे श्री मसाणिग्या भैरव धाम राजगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे। इसके बाद वे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

मनरेगा की आत्मा को खत्म कर रही केंद्र की भाजपा सरकार: डोटासरा

अजमेर, (कासं)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने और इसके मूल स्वरूप में बदलाव के विरोध में सोमवार को अजमेर कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाग लिया।

डोटासरा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा की पहचान और आत्मा को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के कानूनी अधिकार को योजना में बदलकर गरीबों से उनका हक छीना जा रहा है।

शहर जिला कांग्रेस एवं देहात जिला कांग्रेस के संयुक्त आह्वान पर आयोजित धरना प्रदर्शन में जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

अजमेर, (कासं)। प्रगतिशील राजपूत सभा अजमेर की बैठक चामुंडा माता मंदिर परिसर, पुलिस चौकी के सामने आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभा अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने की। बैठक में अध्यक्ष चौहान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतकालीन अवकाश के दौरान 29 एवं 30 दिसम्बर 2025 को जीएलओ खेल मैदान अजमेर में क्रिकेट प्रतियोगिता एवं विभिन्न प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

- सड़क से सदन तक जारी रहेगा संघर्ष: राठौड़
- शहर जिला कांग्रेस एवं देहात जिला कांग्रेस के संयुक्त आह्वान पर आयोजित धरना प्रदर्शन में जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

डोटासरा ने कहा कि पहले ग्राम सभा और जिला परिषद स्तर पर कार्य तय होते थे, लेकिन अब ऊपर से नियंत्रण थोपकर अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला जा रहा है।

उन्होंने घोषणा की कि इस मुद्दे पर आंदोलन की शुरुआत अजमेर से की गई है, जिसे प्रदेश, बूथ और मंडल स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व आरटीडीसी चैयरमैन धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण रोजगार को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ अजमेर से पूरे प्रदेश

में हुंकार भरी जा रही है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विकास चौधरी ने कहा कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही है। पूर्व विधायक रघु शर्मा ने कहा कि अजमेर जिले से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कांग्रेस संगठन को मजबूत कर जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में मंच संचालन सैयद फकरे मोईन व विवेक पाराशर ने किया कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल धरने में महेन्द्र चौधरी, नसीम अख्तर, पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती, महेन्द्र गुर्जर,

रामनारायण गुर्जर, नाथूराम सिनोदीया, रामचन्द्र चौधरी, कमल बाकोलिया, शिवप्रकाश गुर्जर, प्रदेश सचिव सुनिल लारा, वाजिद चीता, शैलेन्द्र अग्रवाल, वाहिद मोहम्मद, चन्दन सिंह, लक्ष्मी धोलखेडीया, शहर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष विजय जैन, भूपेन्द्र राठौड़, नौरत गुर्जर, देशराज मेहरा, जयशंकर चौधरी, मोहित मल्होत्रा, अंकित धारू, सौरभ यादव, इंसाफ अली, मंजू बलार, लक्ष्मी बुंदेल, अनुपम शर्मा, गुलाम मुस्तफा, श्याम प्रजापति, विजय नागौर, दिनेश शर्मा, विपिन बैसील, शैलेश गुप्ता, कमल वर्मा, महेन्द्र तंवर, सौरभ बजाड, देवेंद्र चौधरी, अशोक बिंदल, अभिनव पांडे, अरशद खान, शक्तिप्रताप सिंह, गजेन्द्र सिंह रलावता, सुनिल धानका, नरेश सारवान, मनोज खंडेलवाल, हमिद चीता, चन्द्रशेखर बालोटीया, डॉ ईश्वर राजोरिया, वसीम खान, ईश्वर राजोरिया, चंद्रेश सुनिया आदि उपस्थित रहे।

दिव्यांग बच्चों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है : बिशप स्वामी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान महिला कल्याण मण्डल द्वारा संचालित अद्वैत सेंटर में सोमवार को क्रिसमस पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अजमेर धर्म प्रांत से पधारे फादर जॉन कार्वाल्हो बिशप स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर एचडीएफसी बैंक से नेहा एवं मिताली पारखानी, जुविता फिटनेस केयर से डॉ. किया गिदवानी, राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के निदेशक राकेश कुमार कौशिक, मीनू स्कूल के प्रधानाध्यापक ईश्वर शर्मा, अद्वैत सेंटर का समस्त स्टाफ तथा सागर कॉलेज के विद्यार्थी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अद्वैत सेंटर के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक एवं मनोरंजक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें उपस्थित अतिथियों ने मुक्त कंठ से सराहा। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी को भावभोरा कर दिया।

मुख्य अतिथि फादर जॉन कार्वाल्हो ने बच्चों को आशीर्वाचन देते हुए उनके

- अद्वैत सेंटर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व

उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और असली ईश्वर इन्हीं बच्चों में निवास करता है। समाज को आगे आकर इनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।

राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के निदेशक श्री राकेश कुमार कौशिक ने कहा कि अद्वैत सेंटर दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार की थेरेपी, विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन ईश्वर शर्मा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खेरुनिशा, डॉ. समीक्षा, दीपली, संतोष सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

विधायक कोठारी की प्रेरणा से नेत्रदान

भीलवाड़ा (निर्सं)। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी की प्रेरणा पर 'नर सेवा ही नारायण सेवा है' के ध्येय को चरितार्थ करते हुए, भीलवाड़ा के दुबे परिवार ने शोक और दुःख की अत्यंत कठिन घड़ी में मरणोपरान्त नेत्रदान का प्रोपकारी निर्णय लिया है। संचेती कॉलोनी निवासी मंजू देवी के परिवार ने उनकी स्मृति को अमर बनाने और नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में उजाला भरने के उद्देश्य से नेत्रदान करने का निर्णय लिया। विधायक अशोक कोठारी की निरंतर प्रेरणा और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनके प्रयासों के फलस्वरूप भीलवाड़ा में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

सरवाड़ में शहरी समस्या समाधान शिविर का हुआ आयोजन

सरवाड़ (निर्सं)। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में नगर पालिका परिसर में 16 से 24 तक शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजित हो रहा है वहीं सोमवार को नगर पालिका कार्यालय परिसर में वार्ड संख्या 17 से 20 तक का शिविर का आयोजन किया गया वहीं शिविर के दौरान नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 से 20 में विशेष सफाई अभियान चलाया गया एवं रोड़ लाईट सम्बन्धित नों परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया वहीं शिविर दो महिलाओं को

पूरक पोषाहार के किट वितरण किये गये इस दौरान सोमवार को शिविर में विकसित राजस्थान रथ का आगमन हुआ जिसमें राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी की जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।

रथ में उपलब्ध सुझाव पेटिका में आम नागरिकों ने राज्य सरकार को सुझाव भी प्रेषित किये। शिविर के दौरान शिविर प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता मनीष कुमार बासनीवाल, भागचन्द खटीक, अर्जुन सिंह राठौड़, सहित अन्य उपस्थित रहें।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



2 साल
नव उत्थान - नई पहचान

बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
₹2,000 + करोड़ की स्वीकृति

राज्य परियोजनाओं से कृषकों
को ₹1,200 करोड़ का हस्तांतरण

मुख्य अतिथि

श्री शिवराज सिंह चौहान

माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

अध्यक्षता

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

नागौर जिले में ₹351 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

राशि हस्तांतरण

कृषि एवं उद्यानिकी योजनाएं
31,600 कृषकों को ₹200 करोड़

कृषि आदान-अनुदान
5 लाख कृषकों को ₹700 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
18,500 लाभार्थियों को ₹100 करोड़

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना
4.50 लाख पशुपालकों को ₹200 करोड़

23 दिसम्बर, 2025 | अपराह्न 12:00 बजे | डांगावास, मेड़ता सिटी (नागौर)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

बजरी माफिया से सांठगांठ पर 1 1 पुलिस निरीक्षकों पर गाज गिरी

पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने प्रदेशभर में किया डिकॉय ऑपरेशन

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश में बजरी माफियाओं से सांठगांठ और गंभीर लापरवाही रखने वाले 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा डिकॉय ऑपरेशन करने के बाद यह कार्रवाई हुई। प्रदेशभर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में पांच पुलिस निरीक्षकों को तत्काल निलंबित किया गया है, जबकि छह अन्य को लाइन हाजिर किया

■ **पांच पुलिस निरीक्षक निलंबित, अन्य 6 को लाइन हाजिर किया**

गया है। एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने

आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था,बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी। जांच में दोषी पाए जाने पर 21 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू व बरीनी, अजमेर के पीसांगन और धौलपुर के कोतवाली थाना अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाड़ी व नात्ता, दोसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगारार और जोधपुर पश्चिम के लूणी थाना अधिकारियों को

लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। **बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं :** पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले नवंबर माह में भी सतर्कता शाखा ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उस दौरान जीरो एफआईआर दर्ज न करने, परिवारियों से दुर्व्यवहार, साइबर क्राइम की शिकायतों पर हिलाई, एसपी ऑफिस में प्राप्त परिवारों में परिवाद अनुभाग की कार्यप्रणाली, थाना अधिकारियों की गश्त प्रणाली एवं कार्यशैली और महिला डेस्क पर आने वाली महिलाओं के साथ संवेदनहीन व्यवहार जैसे बिंदुओं पर डिकॉय ऑपरेशन किया गया था।



भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की।

के उद्देश्य से प्रदेशभर में मंडल से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठियां, स्कूलों एवं कॉलेजों में विचार संगोष्ठियां तथा भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी। इसके साथ ही 26 दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान बच्चों को वीरता और शहादत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे तथा साहित्यजादों की शहाबाद व किशनगंज ब्लाक की सहरीया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत लगभग 11 करोड़ की लागत से 22 किमी. सड़क निर्माण कर 11 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है।

गांवों को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2 5 साल पूर्ण हुए

जयपुर (कासं)। स्वतंत्रता के दशकों बाद तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत नींव रखी। जिसके तहत सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आक्विफरी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर

- प्रदेश में 75 हजार से अधिक किलोमीटर सड़कें तथा 68 गुल बनाकर 15983 बसावटों को जोड़ा गया**
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेड़ता में 2089 करोड़ रुपये लागत की 1216 पीएमजीएसवाई सड़कों की सौगात देंगे**

आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मेड़ता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण में प्रदेश की 1216 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने व एक गुल की

सौगात देंगे। जिनकी अनुमानित लम्बाई 3219 किमी. व लागत लगभग 2 हजार 89.37 करोड़ होगी। गौरतलब है कि चौथे चरण में 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश में लगभग 12086 करोड़ रूपये की लागत से 49730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 14043 किमी. सड़कों के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चर्यानित “शू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क” को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सिर्फ नयी सड़कों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़कों के नेटवर्क को और अधिक

मजबूत करना भी आवश्यक है। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1103 करोड़ रुपये की लागत से 3468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण-सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि बाजारों, कॉलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। अब तक प्रदेश में 4060 करोड़ रुपये की लागत से 8549 किमी. की 903 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 पुलों

एम.एन.आई.टी. में प्रस्तावित ट्रेड फेयर पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीपीजे सहित अन्य को जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयुक्त अभिवाचक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में अभिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अगली 16 जनवरी से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और

- बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से प्रस्तावित 3 दिवसीय इस ट्रेड फेयर में सोलर क्षेत्र से जुड़ी दर्जनों निर्माता और सेवा कंपनियां भाग लेंगी**
- याचिका में कहा गया कि, “संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।”**

शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया की एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के परिसर में इस तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि परिसर में बने हॉस्टल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते

“जयपुर ज्वैलरी शो” कला-विरासत और परंपरा का उत्सव : प्रेमचंद बैरवा जे.ई.सी.सी. में जे.जे.एस. संपन्न हुआ, बीते 4 दिनों में करीब 4 6 हजार विजिटर्स ने की शिरकत



जयपुर ज्वैलरी शो के समापन समारोह में सोमवार को उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वैलरी प्रस्तुति के अवार्ड देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

जयपुर (कासं)। जयपुर आभूषण की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है और जयपुर ज्वैलरी शो इस शहर की समृद्ध विरासत, परंपरा और कला का उत्सव है। यह बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर ज्वैलरी शो 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आभूषण उद्योग आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार प्रगतिशील नीतियों और ईएफ ऑफ दूइंग बिजनेस के जरिए इस उद्योग को सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जेजेएस वार्ड्स चेयरमैन दिनेश खटोरिया ने कहा कि अपने शुरुआती

- 18 से 21 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा आगामी संस्करण**

वर्षों में मात्र 67 बूथों से शुरू होकर आज 1227 बूथों तक पहुंचना इस शो की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाता है। आज यह एजोबिशन देश की सबसे बड़ा बी2बी और बी2सी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। जेजेएस के मानद सचिव राजीव जैन ने बेस्ट बूथ अवॉर्ड्स की घोषणा की। उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वेलरी प्रस्तुति के लिए 18 वर्ग मीटर से ऊपर बेस्ट बूथ ज्वेलरी श्रेणी में विजेताओं में पहला स्थान बिरछीचंद घनश्याम दास ने जीता। दूसरे स्थान पर

मोहनलाल नारायणदास ज्वैलर्स रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी (आईआईजीसी) को बेस्ट इंस्टीट्यूट अवॉर्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने शो के अगले संस्करण की तारीखों की भी घोषणा की, जो 18 से 21 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होगा। जैन ने बताया कि इस वर्ष शो में 46 हजार से ज्यादा विजिटर्स आए, जिनमें से 15 हजार बाहर के शहरों से थे। जेजेएस के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता अजय काला ने समापन समारोह का संचालन किया। उन्होंने कहा कि इस बार जेजेएस व्यवसाय के साथ-साथ प्रबंधन की दृष्टि से भी व्यापक और उपयोगी शो रहा। उन्होंने शो की सफलता के लिए सभी प्रदर्शकों, चित्रेताओं और आगंतुकों का आभार जताया।

रिलायंस ज्वैल्स की “ड्रीम डायमण्ड सेल” शुरू

मुंबई। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी “ड्रीम डायमण्ड सेल” फिर से लेकर आए है, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीजन का ख़रन मना सकेंगे। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है। आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरों की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरों की हर खरीद पर 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉपन मिलेगा। इस सीजन की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा। सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर मैकिंग चार्ज पर फ्लैट 20

है और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के प्रावधान है। ऐसे में बिना जांच पड़ताल कंपनियों से जुड़े लोगों को यहां प्रवेश देना उचित नहीं है। ऐसे में इस प्रस्तावित ट्रेड फेयर के आयोजन को रोका जाए। याचिका में पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भरत व्यास व अन्य वकील उपस्थित हुए और उन्होंने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को रखते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है।



फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोजमर्रा के लिए डायमण्ड ज्वेलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटेमेंट स्टायल जैसे चोकर और ब्राइडल डिजाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

राजस्थान में तेल एवं गैस परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर चर्चा

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई ऑनशोर सिक्वोरिटी कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक

जयपुर (कासं)। राज्य में स्थित तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने और पुलिस व ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से गठित ऑनशोर सिक्वोरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस कमेटी में पुलिस, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल समेत सभी ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने सभी ऑयल कंपनियों को स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के साथ निरंतर समन्वय से समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी

आवश्यकता जताई। बैठक में विभिन्न ऑयल कंपनियों द्वारा की गई मांगों के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में सजग प्रहरी प्रोत्साहन योजना, पुलिस के साथ जोईंट नेट्रोलिंग, पुलिस नाकाबंदी, चेक पॉइंट्स तथा नियमित सिक्वोरिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, ड्रोन श्रेट के लिए एसओबी, नो-ड्रोन जोन चर्च की घोषणा तथा राजस्थान ऑनशोर सिक्वोरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पुनर्गठन संबंधित विषयों पर भी चर्चा

- डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय अग्रवाल ने डिजिटल पोर्टल विकसित करने, उपलब्ध रिसोर्स की मैपिंग तथा सभी ऑयल कंपनियों के लिए एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता जताई।**

चुनौती के प्रभावी समाधान के लिए रियल टाइमरिपोर्टिंग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऑयल चोरी जैसे अपराधियों से संबंधित मजबूत और अद्यतन डेटा बेस तैयार करने तथा ऑयल

पाइपलाइन संपूर्ण देश एवं राज्य के आधारभूत परिदृश्य को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय अग्रवाल ने ऑयल कंपनियों की ओर से सूचनाओं के व्यवस्थित संधारण

के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने तथा उपलब्ध रिसोर्स की मैपिंग करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी ऑयल कंपनियों के लिए एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने की



जयपुर । सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला-2025 में वीकेंड के बाद भी उत्साह और चहल-पहल कम नहीं हुई। सोमवार को मेले के पाँचवें दिन सामान्य कार्यदिवस होने के बावजूद मेला परिसर में भीड़ देखने को मिली। शिल्प, हस्तकला और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि ने मेले को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया। परिवारों के साथ आए दर्शकों ने विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इसी क्रम में टाइनी टॉट्स इंग्लिश स्कूल के स्कूली बच्चों ने भी मेले का भ्रमण किया। बच्चों ने महिला उद्यमिता, ग्रामीण आजीविका और स्वदेशी उत्पादों की नजदीक से समझा, जो उनके लिए आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव रहा। महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मेले के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा कमला पोद्दार ग्रुप के सहयोग से एक विशेष उत्पाद संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसएचजी महिलाओं को डिजाइन नवाचार, गुणवत्ता सुधार और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद विकसित करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया।

</

